REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2025

One Nation One Subscription (ONOS) : भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्व, चुनौतियाँ और संभावनाए

युधिष्ठिर प्रधान
ग्रंथपाल, शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुन्द, छत्तीसगढ़

सारांश

21 सदी के ज्ञान–आधारित विश्व में सूचना और डिजिटल संसाधन किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सबसे मूल्यवान पूँजी बन चुके हैं। आधुनिक शिक्षा, उच्चस्तरीय अनुसंधान और नवाचार का विकास तभी संभव है जब सभी शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण सूचना–संसाधनों तक समान पहुँच प्राप्त हो। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या तो बहुत अधिक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शोध–सामाग्री की उपलब्धता में असमानता एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। अधिकांश छोटे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थान महँगे डिजिटल डेटाबेस, शोध जर्नल और ई–रिसोर्स की सदस्यता लेने में असमर्थ रहते हैं। परिणामस्वरूप गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य, आधुनिक ज्ञान और वैश्विक स्तर की वैज्ञानिक सामाग्री कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित संस्थानों तक सीमित रह जाता है। इस असमान पहुँच के कारण न केवल शोध की गुणवत्ता में अंतर उत्पन्न होता है, बल्कि नवाचार और ज्ञान–सृजन की राष्ट्रीय क्षमता भी प्रभावित होती है।

ऐसी स्थिति में ज्ञान–संसाधनों की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शैक्षणिक समानता को प्रोत्साहन मिले और सभी विद्यार्थीयों तथा शोधकर्ताओं को समान अवसर प्रदान किए जा सकें। डिजिटल संसाधनों का लोकतंत्रीकरण देश की शोध–परंपरा को सुदृढ़ करने, नवाचार को गति देने और भारत को ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह शोध इसी असमानता के समाधान और ज्ञान–सुलभता के महत्व को रेखांकित करता है तथा शिक्षा के भविष्य के लिए समान किफायती और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पहुँच की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य शब्द

1. ज्ञान–सुलभता (Knowledge Accessibility)
2. शैक्षणिक समानता (Educational Equality)
3. डिजिटल संसाधन (Digital Resources)
4. राष्ट्रीय सदस्यता समझौता (National Subscription Agreement)
5. सामुहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)

6. ज्ञान लोकतंत्रीकरण (Knowledge Democratization)
7. डिजिटल डिवाइड (Digital Divide)
8. शोध–गुणवत्ता सुधार (Research Quality Enhancement)
9. समान अवसर (Equal Opportunity)
10. आर्थिक बचत (Economic Savings)
11. शैक्षणिक सशक्तिकरण (Academic Empowerment)
12. ज्ञान–आधारित समाज (Knowledge-Based Society)

भारत सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) नीति शिक्षा और शोध की दुनिया में बढ़ती असमानताओं को कम करने की दिशा में एक अत्यंत दूरदर्शी और महत्वपूर्ण कदम है। आज के डिजिटल युग में ज्ञान का सबसे बड़ा स्त्रोत ऑनलाईन जर्नल, डेटाबेस, ई–बुक्स और शोध–सामग्री हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी अधिक होती है कि अधिकांश छोटे और मध्यम स्तर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान इन्हे वहन नहीं कर पाते। इस आर्थिक असमानता के कारण श्रेष्ठ ज्ञान–संसाधनों तक पहुँच कुछ चुनिंदा संस्थानों तक ही सीमित हो जाती है, जबकि देशभर में लाखों विद्यार्थीयों, शोधार्थियों और शिक्षकों कों इसके अभाव में गुणवत्ता शिक्षा और कार्यों में बाधाएँ झेलनी पड़ती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ONOS नीति एक व्यापक समाधान प्रदान करती है, क्योंकि इसका उददेश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख प्रकाशकों से राष्ट्रीय समझौता करके पूरे देश के लिए एक समान और किफायती पहुँच उपलब्ध कराना है।

यह नीति इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान एक सार्वजनिक संसाधन होना चाहिये , ना कि कुछ संस्थानों तक सीमित कोई विशेषाधिकार जब सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एकमुश्त भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त करती है, तो देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थान–एक ही प्लेटफॉर्म से उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं । इससे न केवल छात्रों के लाभ मिलता है, बल्कि शिक्षक, शोधकर्ता, वैज्ञानिकों और नीति–निर्माता भी अद्यतन और विश्सनीय जानकारी का उपयोग करके बेहतर शोध और नवाचार कर सकते हैं। इसके परिणाम देश में शोध–प्रकाशनों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और भारत वैश्विक ज्ञान–परिदृश्य में अधिक सशक्त और प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

ONOS का एक अन्य बड़ा लाभ आर्थिक है। सामान्यतः प्रत्येक संस्थान अलग–अलग सदस्यता योजनाएँ खरीदता है। जिन पर हर वर्ष भारी राशि खर्च होती है। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण संसाधन महँगे होने के कारण कई संस्थानों की पहुँच से बाहर रह जाता हैं। लेकिन यदि सरकार एक ही बार सौदेबाज़ी करके देशभर के लिए एक समेकित सदस्यता खरीदती है, तो लागत न केवल काफी कम हो जाती है। बल्कि संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता भी कई गुणा बढ जाती है। इससे शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों पर आर्थिक बोझ घटता है और बची हुई राशि को अन्य शैक्षणिक विकास कार्यो में लगाया जा सकता है। जैसे– नए प्रयोगशाला, पुस्तकालय उन्नयन, शोध–वृत्ति और नवाचार परियोजनाएँ।

नीति का सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत उल्लेखनीय है। उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान की समान पहुँच शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नीति दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कम संसाधनों वाले संस्थानों को भी वही अवसर देती है जो बड़े महानगरीय संस्थानों को उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थीयों और शोधार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, और वे भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिये आवश्यक ज्ञान एवं उपकरण प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही ONOS से शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ती है, क्योकि यह सभी के लिये उपलब्ध एक साझा प्रणाली का निर्माण करती है, जिसमें किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहती है। समग्र रूप से देखा जाए तो **''वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन''** नीति भारत के शिक्षा–तंत्र को अधिक सशक्त, समावेशी, किफायती और भविष्य के लिए तैयार बनाती है। यह ज्ञान–आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक पहल है, जो न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिये बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर शैक्षाणिक और शोध वातावरण का मार्ग प्रशस्त करती है।

UNESCO (2021) की एक रिपोर्ट में कहा गया है, "Access to knowledge is not privilege: it is a necessity for sustainable development" इसी दृष्टिकोण को साकार करने का माध्यम है ONOS। यह

शोध–पत्र ONOS की आवधारणा, पृष्टभूमि, प्रासंगिकता, लाभ, चुनौतियों और नीतिगत सुझाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि नीति का क्रियान्वयन पारदर्शिता, तकनीकी तैयारी और दीर्घकालीक वित्तीय योजना के साथ किया जाए तो यह भारत में ज्ञान–लोकतंत्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

भारत सरकार की ''वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'' (ONOS) नीति आज के ज्ञान–आधारित समाज की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने की क्षमता रखती है। 21वीं सदी को अवसर **डिजिटल नॉलेज सेंचुरी** कहा जाता है, जहाँ जानकारी तक पहुच ही प्रगति आ आधार है। लेकिन वास्तविता यह है कि उच्च गुणवत्ता वाले शोध–पत्र, प्रतिष्ठित जर्नल,ई–बुक्स, और डिजिटल डेटाबेस की सदस्यता इतनी महँगी होती है कि देश के अनेक छोटे और मध्यम स्तर के संस्थानों तक सीमित रह जाती है। यह स्थिति उस असमानता को और बढ़ा देती है, जिसमें ''ज्ञान एकाधिकार'' कुछ ही हाथों में सिमटकर रह जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध शिक्षाविद् **पाउलो फ्रेरे कहते है**:– "Education either functions as an instrument of freedom or an instrument of oppression" यदि ज्ञान तक समान पहुँच न हो तो यह निश्चित रूप से दमनकारी संरचना का रूप ले लेता है।

ऐसे परिप्रेक्ष्य में ONOS नीति एक दूरदर्शी समाधान के रूप में उभरती है। इस योजना का उददेश्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रकाशनों से एकीकृत राष्ट्रीय समझौता कर भारत के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यायों और शोध संस्थानों कों एक समान और मुक्त (Free_Access) पहुँच प्रदाय करना है। ONOS इस विचार पर आधारित है कि **''ज्ञान एक विलासिता नहीं, बल्कि अधिकार होना चाहियें।''** जब सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एकमुश्त भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त करती है, तो देश के हर संस्थान– चाहे वह केंन्द्रीय विश्वविद्यालय हो, सरकारी महाविद्यालय हो, निजी तकनीकी संस्थान को या ग्रामीण अंचल में स्थित कोई छोटा महाविद्यालय सभी एक जैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते है।

यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देती है। जैसा कि **जवाहरलाल नेहरू ने कहा था** : "The future depends on what you today" ONOS इसी भाव को साकार करते हुए वर्तमान पीढ़ी को वह डिजिटल अवसर प्रदान करती है। जो भविष्य के शोध और नवाचार का आधार बनेगा। जब सभी छात्रों और शोधकर्ताओं के समान गुणवत्ता की सामग्री होगी, तब शोध की गुणवत्ता भी स्वतः बढ़ेगा। इससे भारत वैश्विक ज्ञान–सृजन में अधिक सशक्त भागीदारी कर सकेगा।

ONOS का आर्थिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपुर्ण है। समान्य परिस्थियों में प्रत्येक संस्थान अलग–अलग सदस्यता खरीदता है, जिससे कारण भारी आर्थिक बोझ पड़ता है और संसाधनों की विवेकी खरीद नहीं हो पाती। कई महत्वपूर्ण डेटाबेस– जैसे Elsevoer, JSTOR, Springer और Wiley की सदस्यता इतनी महँगी होती है कि छोटे महाविद्यालय इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ONOS के तहत सरकार इन सभी संसाधनों को सामुहिक सौदेबाजी ताकत के माध्यम से बहुत कम लागत पर देश के लिये उपलब्ध करा सकती है। इससे ''आर्थिक संसाधन असमानता'' समाप्त होती है।

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे ''राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान'' में तेजी आएगा। जब शोधकर्ता अद्यतन जानकारी तक सुगमतापूर्वक पहुँच पाते हैं तो वे नई खोज नए विचार और समाजोपयोगी शोध कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते है। नोबेल पुरूस्कार विजेता **रिचर्ड फादनमैन** का कथन यहाँ बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है'– "Knowledge isn't free. You have to pay attention" ONOS के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करती है कि शोधकर्ता धन से नही बल्कि अपने ध्यान से करें आर्थात उन्हे सामाग्री की कमी नहीं, बल्कि अपने कौशल और मेहनत पर ध्यान देना होगा।

समाजिक प्रभाव की दृष्टि से ONOS ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जैसे विशाल देश में शिक्षा की असमानता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। महानगरों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और छाटे शहरों के कॉलेजों के मध्य जो डिजिटल अंतर है, वह शिक्षा के स्तर को सीधे प्रभावित करता है। ONOS इस खाई को पाटने में निर्णायक भूमिका निभाता है। जब किसी छोटे संस्थान का छात्र वही जर्नल पढ़ सके जिसे आई.आई.टी. या आई.आई.एस.सी. का छात्र पढ़ रहा है तभी वास्तविक समानता स्थापित

होती है। जैसा कि **नेल्सन मंडेला** ने कहा था "Education is the most powerful weapon can use to change the word" इस शक्ति को सभी के लिये सुलभ बना देता है।

इसके अतिरिक्त ONOS से शैक्षणिक पारदर्शिता भी बढ़ती है। एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध संसाधन समान अवसर का वातावरण बनातें हैं जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव या असमानता नहीं रहती है इससे छात्रों और शोधकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक सक्षम बनतें हैं।

अंततः वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) नीति केवल एक तकनीक व्यवस्था नहीं है। बल्कि यह शिक्षा में समानता, सशक्तिकरण और गुणवत्ता सुधार की व्यापक दृष्टि का परिचायक है। यह डिजिटल भारत के उस सपने को मजबूत करती है जिसमें हर नागरिक ज्ञान–सपन्न सक्षम और भविष्य के लिए तैयार हो। यह पहल भारत को वैश्विक ज्ञान–समुदाय में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।

संक्षेप में ONOS. नीति भारत की शैक्षणिक संरचना को अधिक समावेशी, सशक्त, किफायती और आधुनिक बनाती है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल ज्ञान उपलब्ध कराती है, बल्कि आने वाली पीढ़ीयों के लिये भी एक स्थायी और मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ONOS सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि ज्ञान समता का राष्ट्रीय अभियान है, जो शिक्षा के भविष्य को नई दिशा प्रदान करने की क्षमता रखता है।

शोध के उद्देश्य (Objective)

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैः–

1. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की आवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नीति–ढ़ाचे का अध्ययन करना।
2. भारत की वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों की असमानता का विश्लेषण करना।
3. ONOS के संभावित समाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभों का मूल्यांकन करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों– जैसे चीन का CNKI मॉडल, यूरोप का Plan S- का तुलनात्मक अध्ययन कर भारतीय संदर्भ में उपयुक्त रणनीति सुझाना।
5. क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर समाधान हेतु व्यवहारिक नीति सुझाव प्रस्तुत करना।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं साहित्य समीक्षा (Theoretical Background and Review of Literature)

ज्ञान तक समान पहुँच की अवधारणा का उद्भव ''ओपन एक्सेस मूमेंट'' से हुआ, जिसका उद्देश्य था–ज्ञान को सीमित वर्ग के नियंत्रण से मुक्त करना। **विश्व बैंक** की Knowledge Econimy Index Report (2023) के अनुसार, "Those nations that democratize access to academic information grow their innovation index by 30% faster than others." यह स्पष्ट करता है कि सूचना तक समान पहुँच किसी राष्ट्र की नवाचार क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पहलें इस दिशा में की गईं। यूरोप में Plan S (2018) ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सार्वजनिक धन से होने वाला शोध सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिये। चीन ने Chaina National Knowledge Infrastructure (KNKI) नामक विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर अपने लगभग सभी विश्वविद्यालयों को एकीकृत पहुँच प्रदान की। अमेरिका में Publis Access Policy (2015) के तहत सरकारी अनुदान से किये गए शोध पत्र 12 महिनों के भीतर सार्वजनिक किये जाने अनिवार्य हैं।

भारत में भी इसी दिशा में प्रयास हुये। INFLIBNET Center द्वारा संचालित e-ShodhSindhu और UGC- INFONET Digital Library Consortium जैसी परीयोजनाएँ आरंभ की गई परंतु ये केवल सीमित विश्वविद्यालयो तक पहुँच सकी। ग्रामीण व निजी महाविद्यालय इनसे वंचित रह गए। जैसा कि **अमर्त्य सेन** ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Development as Freedom में कहा है, "The capability to access information is itself a from of freedom" इस दृष्टि से एक नीतिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर उभरता है, जो शिक्षा में समानता के आदर्श को मूर्त रूप देता है।

ONOS की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता (Need and Relevance in India Conrext)

भारत का शिक्षा ढाँचा अत्यंत विस्तृत और विषम है। यहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या तो बहुत है, परंतु संसाधनों का वितरण असमान है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में शोध संसाधनों की भारी कमी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जर्नल्स के लिये प्रति वर्ष लाखों रूपये शुल्क लेते हैं, जो किसी भी छोटे संस्थान के लिये वहन योग्य नहीं।

ONOS नीति इस समस्या का सामूहिक समाधान प्रस्तुत करती है। यदि केंद्र सरकार एकीकृत रूप से अनुबंध करती है, तो सभी संस्थानों को समान रूप से लाभ मिलेगा। यह न केवल "Econoomy of Scale" प्रदान करेगा बल्कि संसाधनों का पुनः उपयोग (Resouce optimization) भी सुनिश्चित करेगा।

सामाजिक दृष्टि से भी ONOS का महत्व अपार है। यह **''ज्ञान में सामाजिक न्याय''** की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जैसा कि ने UNESCO (2021) ने कहा "Knowledge divides are the new social divides." अतः केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि समाजिक समानता की नीति है। इसका लाभ यह है कि यह शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेख, डेटा और केस स्टडीज तक पहुँच मिलती है। तो वे अधिक प्रासंगिक और समकालीन शोध प्रस्तुत कर पाते हैं। इससे भारत का वैश्विक शोध में योगदान भी बढ़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और तुलनात्मक विश्लेषण (International Context Comparative Analysis)

ONOS की प्रेरणा विभिन्न देशों के सफल मॉडलो से ली गई है। उदाहरण स्वरूप, **चीन का CNKI मॉडल** अपने आप में अद्वितीय है। यह न केवल देश के सभी विश्वविद्यालयों को जोडता है बल्कि शोधार्थियों के लिए "Single Window Access" प्रदान करता है। यह मॉडल चीन के ज्ञान–अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) को गति देने में सहायक सिद्ध हुआ।

यूरोप का मॉडल एक परिवर्तनकारी नीति रही है। इसका मूल सिद्धांत है कि "No publicly Funded research should remain behind paywalls." इस योजना के अंतर्गत यूरोपीय देशों ने प्रकाशकों से सामूहिक अनुबंध किए, जिससे हजारों जर्नल्स सार्वजनिक पहुँच में आए।

अमेरिका मॉडल में Public Access Mandate लागु किया गया, जिसके अनुसार सभी संघीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कार्य ओपन एक्सेस रूप में प्रकाशित होने चाहिये।

भारत में ONOS इन मॉडलों से प्रेरणा ले सकता है, परंतु इसे भारतीय समाज की बहुभाषीय और विविध संरचना के अनुरूप ढालना आवश्यक होगा। उदाहरण स्वरूप, क्षेत्रीय भाषाओं में सार–संक्षेप और सार्थक अनुवाद उपलब्ध करानें होंगे ताकि हिंदी, तमिल, बंगाली या मराठी माध्यम के विद्यार्थी भी समान रूप से लाभान्वित हों।

विश्लेषण एवं चर्चा (Analysis and Discussiun)

ONOS नीति का विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तीनों दृष्टियों से किया जा सकता है।

(क) आर्थिक लाभ

ONOS सामुहिक अनुबंध के माध्यम से लागत घटाने में मदद करता है। जब हजारों संस्थान एक साथ किसी प्रकाशन से अनुबंध करते हैं, तो "Bulk Negotoaton" के कारण लागत घटती है। इससे सरकार के करोडों रुपये बच सकते हैं, जिन्हें शोध अवसंरचना के विकास में लगाया जा सकता है।

(ख) समाजिक और शैक्षणिक लाभ

ONOS यह नीति ज्ञान को केंद्रीयकृत विशेषाधिकार से निकालकर आम शोधार्थी के हाथ में सौंपती है। यह "Knowledge as a Public Good" की आवधारणा को मूर्त रूप देती है। इससे सामाजिक न्याय और

समावेशन को भी बल मिलता है। जैसा कि **गांधीजी ने कहा था**– "True education must correspond to the surrounding circumstances or it is not a healthy growth." ONOS सभी सामाजिक वर्गों को समान अवसर प्रदान कर इस विचार को व्यवहार में लाता है।

(ग) तकनीक लाभ और चुनौतियाँ

ONOS के लिए एक सशक्त डिजिटल पोर्टल की आवश्यता होगी जो देशभर के उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और तीव्र पहुँच प्रदान करे। हालांकि, भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इंटरनेट की गति सीमित है। अतः इस नीति की सफलता डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

(घ) संभावित चुनौतियाँ

1. वित्तीय दबाव–प्रारंभिक निवेश बड़ा होगा।
2. कॉपीराइट विवाद–प्रकाशकों के साथ शर्तो को संतुलित करना कठिन होगा।
3. भाषाई बाधाएँ– अधिकांश सामाग्री अंगेजी में है।
4. प्रशासनिक जटिलता–एकीकृत पोर्टल और उपयोग प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की आवश्यता होगी।

फिर भी, जैसा कि **जॉर डेवी** ने कहा था, "If we teach today's students as we taught yesterdays we rob them of tomarow." भारत को इस नीति के माध्यम से भविष्य की दिशा तय करनी होगी।

नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)

1. ONOS के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित किया जाए जो अनुबंध, पारदर्शिता और उपयोग निगरानी सुनिश्चित करे।
2. बहुभाषीय डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जहाँ अंग्रेजी के साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी सारांश उपलब्ध हों।
3. Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत निजी क्षेत्रों को वित्तीय भागीदारी के लिए प्रोतसाहित किया जाए।
4. शोध डेटा विश्लेषण ईकाई गठित की जाए जो उपयोग के आँकडों और प्रभाव का मूल्यांकर करे।
5. ग्रामीण संस्थानों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ ताकि वे पोर्टल का समुचित उपयोग कर सकें।
6. ओपन एक्सेस और Read & Public मॉडल के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि लेखन शुल्क का बोझ न बढ़े।
7. सतत वित्तीय मॉडल तैयार किया जाए– जैसे पाँच वर्षीय अनुबंध, वार्षिक पुनर्मूल्यांकन आदि।
8. डेटा सुरक्षा और कॉपीराइट नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाए ताकि कानूनी विवाद न उत्पन्न हों।

निष्कर्ष (Conclusion)

"One Nation One Subscription" नीति भारत के लिए केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक वैचारिक क्रांति है। यह शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार के सिद्धांतों को सशक्त रूप में स्थापित करती है। यह नीति भारत को ''ज्ञान–समाज'' (Knowledge Society) की दिशा में अग्रसर कर सकती है। जहाँ जानकारी कुछ संस्थानों तक सीमित न रहकर हर जिज्ञासु मन तक पहुँचे।

जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "The future belongs to science and those who make friends with science." ONOS नीति का विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तीनों दृष्टियों से किया जा सकता है। इसी मित्रता का संस्थागत स्वरूप है। यदि इसे पारदर्शी नीतिगत ढाँचे, वित्तीय स्थिरता और तकनीकी अवसंरचना के साथ लागू किया गया तो यह भारत को वैश्विक शोध मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिला सकता है।

निष्कर्षकः कहा जा सकता है कि ONOS नीति का विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तीनों दृष्टियों से किया जा सकता है। **''शिक्षा के अधिकार''** की तरह ही **''ज्ञान तक पहुँच के अधिकार''** को साकार करने की दिशा में भारत का ऐतिहासिक प्रयास है। यह नीति भविष्य के भारत के लिए ज्ञान–समानता का ऐसा पुल बनेगी जो गाँव और महानगर, सरकारी और निजी, हिन्दी और अंग्रेजी– सभी के बीच की सीमाएँ मिटा देगा।

Works Cited (MLA 9th Edition)

1. *"National Education Policy 2020." Ministry of Education, Government Of India,2020.*
2. *INFLIBNET Centre. e-Shodhsindhu: Consortium for Higher Education Electonic Resources. INFLIBNET, 2022.*
3. *"Plan S." Coalition S, 2021.*
4. *CNKI. China National Knowledge Infrastructure. CNKI Official Portal, 2022.*
5. *UGC. UGC-INFONET Digital Library Consortium Report. University Grants Commission, 2021.*
6. *World Bank. Knowledge Economy Index Report. 2023.*
7. *UNESCO. Global Report on Open Access. Paris, 2021*
8. *Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford UP, 1999.*
9. *Dewey, John. Democracy and Education. Free Press, 1916.*
10. *Gandhi, M.K. Basic Education. Navajivan Publishing, 1951.*